भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2714
(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बड़ौदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का कार्यकरण

2714. **श्री आदित्य यादव:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़ौदा ज़िले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत आवास का निर्माण, स्वच्छता सुविधाओं का संचालन तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मज़दूरी का भुगतान आदि कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण विकास के कार्यों में तेज़ी लाने, स्वच्छता सुविधाओं को शुरू करने और समय पर मज़दूरी के भुगतान के लिए किए जा रहे प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय गुजरात के बड़ौदा जिले सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ/कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) कार्यान्वित कर रहा है।

उपरोक्त सभी योजनाएँ/कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के समन्वय से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है और कार्यों के समय पर पूरा होने और मज़दूरी भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ कही भी देरी या अनियमितताएँ पाई जाती हैं वहां सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

*****